

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5118
02 अप्रैल, 2025 को उत्तर देने के लिए

भारतीय अनुसंधानकर्ताओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

†5118. श्री पी. सी. मोहन:

श्रीमती स्मिता उदय वाघ:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने भारतीय अनुसंधानकर्ताओं, छात्रों और पेशेवरों हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों का समर्थन करने के लिए कदम उठाए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (ग) प्रतिभा पलायन को रोकने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसरों का सृजन कर और देश के भीतर रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित कर अनुसंधानकर्ताओं की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ख): विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारतीय अनुसंधानकर्ताओं, छात्रों और पेशेवरों हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करने के लिए समझौता जापन (एमओयू), आशय पत्र (एलओआई), सहयोग कार्यक्रम (पीओसी) या अन्य करारों जैसे साधनों के माध्यम से 40 देशों के साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष के सभी प्रमुख क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान कर रहा है। प्रत्येक वर्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय सहयोग सहित बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) प्रस्तावों के लिए लगभग 16 संयुक्त आह्वान करते हैं। इंडो-फ्रैंच सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एडवांस्ड रिसर्च (सीईएफआईपीआरए), इंडो-जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर (आईजीएसटीसी) और इंडो-यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम (आईयूएसएसटीएफ) जैसे द्विराष्ट्रीय निकाय अनुसंधान समुदाय के लिए विभिन्न प्रकार के सहयोगी अवसर प्रदान करते हैं। डीबीटी - इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रंटियर साइंस प्रोग्राम ऑर्गनाइजेशन (एचएफएसपीओ) और वेलकम ट्रस्ट (यूके) के साथ बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम (बीआरसीपी) जैसे सहयोगी साझेदारी कार्यक्रम, अध्येतावृत्ति कार्यक्रम हैं जिनका लक्ष्य

उच्च गुणवत्ता वाले जैविक अनुसंधान को सहायित करना है। भारत जर्मनी में एंटीप्रोटोन और आयन अनुसंधान सुविधा (एफएआईआर), अमेरिका में थर्टी मीटर टेलीस्कोप (टीएमटी), ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में स्क्वायर किलोमीटर और (एसकेए) जैसी अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाओं में भी भाग ले रहा है जहां भारत दुनिया भर के कई अग्रणी देशों के साथ मिलकर कार्य करता है। भारत यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन (सर्न, जिनेवा); एलीट्रा सिंक्रोट्रॉन (इटली); एसपी-रिंग-४ (जापान); कईके एक्सेलरेटर (जापान); फर्मि-लैब (यूएस); सिंक्रोट्रॉन लाइट सोर्स (ब्राजील और सिंगापुर); सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन सोर्स बीम-लाइन (रूस) आदि का भी हिस्सा है। इन सहयोगों से संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं, सेमिनारों, अध्येतावृत्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अनुसंधान क्षमता वर्धन और अवसंरचना के विकास, विनिमय और एक्सपोजर यात्राओं, उन्नत सुविधाओं तक पहुँच, प्रौद्योगिकी अंतरण, संयुक्त प्रकाशन आदि को सुकर बनाने में सहायता मिली।

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रतिभा पलायन को रोकने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसरों का सृजन करने तथा देश के भीतर रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कई योजनाएं तैयार की हैं। डीएसटी अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष (इंस्पायर) संकाय योजना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए आकर्षक मार्ग और अवसर प्रदान करता है। कुछ शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान संकाय सदस्यों/वैज्ञानिकों को देश में नियमित नौकरी में रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओं में अनुसंधान पद ग्रहण करने हेतु अवकाश प्रदान करते हैं। वैश्विक मेंगा अनुसंधान अवसंरचना सुविधाओं में भागीदारी हमारे अनुसंधानकर्ताओं को उन्नत सुविधाओं तक पहुँच और मेंगा-विज्ञान/संघ परियोजनाओं में भागीदारी हेतु सक्षम बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अवसर और हमारे अनुसंधान एवं शैक्षणिक क्षेत्र में परिष्कृत अनुसंधान अवसंरचना सुविधाओं की उपलब्धता देश में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधानकर्ताओं को बनाए रखने और प्रतिभा पलायन को रोकने में सहायता करती है।
